भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4352** जिसका उत्तर

गुरूवार, 19 **मार्च**, 2020/29 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है

अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में गंगा नदी का विकास

4352. श्रीमती क्वीन ओझाः

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गंगा नदी को अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में विकसित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस पर कितना व्यय किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का उक्त जलमार्गों पर रो-रो फेरी और रो-पैक्स फेरी संचालित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) एवं (ख): जी, हां। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-1 के हल्दिया-वाराणसी जलखंड पर नौचालन के क्षमता आवर्धन के लिए 5369.18 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) को कार्यान्वित कर रहा है। जेएमवीपी के मुख्य मध्यवर्ती कार्यों में वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनलों का निर्माण; फरक्का में नौचालनात्मक लॉक; 2.2 से 3 मीटर की न्यूनतम निश्चित गहराई (एलएडी) के प्रावधान हेतु फेयरवे विकास कार्य; नदी सूचना प्रणाली(आरआईएस) आदि शामिल हैं। वैधानिक अनुमतियां प्राप्त होने के बाद तीन वर्षों की समयावधि में 1800 करोड़ रु. (लगभग) की परियोजनाएं वास्तविक रूप से शुरू हो गई हैं तथा दिनांक 29.02.2020 तक 1566.99 करोड़ रु. का व्यय हो चुका है।

(ग): जी, नहीं। तथापि, जेएमवीपी के मध्यवर्ती कार्यों में राजमहल (झारखंड) - मानिकचक (पश्चिम बंगाल), समदघाट (झारखंड) - मनिहारी (बिहार), कहलगांव - तीनटंघा (बिहार), हसनापुर-बख्तियारपुर (बिहार), बक्सर (बिहार) - सरायकोटा (उत्तर प्रदेश) में रो-रो टर्मिनलों के पाँच जोड़े शामिल हैं, जिनकी सूचना इनका संचालन करने हेतु आवश्यक अवसंरचना स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों सहित संभावित हितधारकों को दे दी गई है।

*****